>

Title: Need to provide adequate pay and allowances and other service benefits to Grameen Dak Sevaks in the country.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): भारतीय डाक विभाग में लगभग एक लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिसों में से लगभग एक लाख 30 हजार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिसों का संचालन लगभग 3.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की डाक सेवाओं द्वारा स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, इलेक्ट्रानिक मनीआर्डर, इंश्योरेंस पार्सल, बचत खाता संचालन, सावधि जमा योजना, एनएससी तथा भारतीय पोस्टल आर्डर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।

वर्तमान में ग्रामीण डाक सेवकों को अत्यंत नगण्य वेतन दिया जा रहा है। किसी वेतन आयोग द्वारा इन ग्रामीण डाक सेवकों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाना अत्यंत आश्चर्यजनक है। पिछले एक दशक में मुद्रास्फीति (महंगाई) 60 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है परंतु इनके वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह अत्यंत क्षोभ का विषय है कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को विभाग किसी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा, ट्यूशन फी, नई पेंशन स्कीम, एलटीसी सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है।

महिला केन्द्रीय कर्मचारी को गर्भवती होने पर 6 माह की एवं बच्चे के पालन-पोषण हेतु 765 दिन की छुट्टी देय है परंतु ग्रामीण डाक सेवक महिलाओं को इन सुविधाओं से भी वंचित रखना वस्तुतः नारीत्व का अपमान है।

शहरी क्षेत्र में काम करने वाले पोस्टमैन को छाता, वर्दी, बैग एवं जूते उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु ग्रामीण डाक सेवकों को इन सब सुविधाओं से वंचित रखना अन्याय है।

मेरी मांग है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतनमान एवं उनको दी जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी कर केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर अपनी कल्याणकारी योजनाओं यथा मनरेगा, छात्रवृत्ति, विधवा एवं वृद्धा पेंशन में इन ग्रामीण डाक सेवकों का उपयोग करे।